

# **भारत का राजपत्र** **The Gazette of India**

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २७]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई ३, १९७१/आषाढ़ १२, १८९३

No. 27]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 3, 1971/ASADHA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## भाग II—खण्ड ३—उपखण्ड (ii)

### PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर)

केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गए विधिवत आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

(MERCHANT SHIPPING)

New Delhi, the 10th June, 1971

S.O. 2500.—In pursuance of rule 5 of the Indian Merchant Shipping Seamen's Employment Office, Calcutta) Rules, 1954, the Central Government hereby appoints Shri S. Puri as a member of the Seamen's Employment Board (Foreign-going) at the port of Calcutta to represent the Shipowners for the remaining term of office of Shri P. I. D. Barty, resigned and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) S.O. No. 2027, dated the 28th May, 1970, namely:—

In the said notification, in Serial No. 8, for the entry 'P.I.D. Barty', the entry 'S. Puri' shall be substituted

[15-MT(2)/69.]

HARBANS SINGH, Dy. Secy.

## पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 10 जून, 1971

(व्यापार पोतपरिवहन)

सं. ओ० 2500—भारतीय व्यापार पोतपरिवहन (नाविक रोजगार कार्यालय, कलकत्ता) नियम, 1954, के नियम 5 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एस० पुरी को पोतमालिकों के प्रतिनिधि के रूप में श्री पी० आई० डी० बार्टी, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, की शेष पदावधि के लिए कलकत्ता पत्तन पर नाविक रोजगार बोर्ड (विशेषगामी) का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० ओ० 2027, दिनांक 28 मई 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 8 में प्रविष्टि पी० आई० डी० बार्टी के स्थान में प्रविष्टि “एस० पुरी” प्रतिस्थापित की जाएगी।

[15-एमटी (2)/69]

हरबंस सिंह, उप सचिव।

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 9th June 1971

S. O 2501—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Servants (Discipline and Appeal) Second Amendment Rules, 1971.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Schedule III to the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968,—
  - (i) in column three, against item Nos. 1 and 2 for the expression ‘General Managers and; Director General, R.D.S.O. the following expression shall be substituted, namely :—  
“General Managers, Director General, R.D.S.O. and Chief Administrative Officers.”
  - (ii) after item No. 2, the following item shall be inserted, namely :—

Item No.	Class of Railway Servants	Authority empowered to place a railway servant under suspension or to impose penalties and its nature	Appellate authority
3.	Railway Servants not classified either as Class I or Class II, viz. Temporary Assistant Officers.	President—Full powers Railway Board—Full Powers General Managers, Director General RDSO and Chief Administrative Officers	— President. Railway Board.

[No. E (D &amp; A) 70 RG 6-63]

C. S. PARAMESWARAN,

Secy. Railway Board &amp; officiating Jt. secy. Govt. of India.

## रेल मंत्रालय

## (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 9 जून, 1971

एस० ओ० 2501.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) ये नियम, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) द्वितीय संशोधन नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 की अनुसूची III में—

(i) कालम तीन के मद 1 और 2 के सामने “महा प्रबन्धक और महानिदेशक अनुसंधान अभिकल्प तथा मानक संगठन” के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

“महा प्रबन्धक, महानिदेशक अनुसंधान, अभिकल्प तथा मानक संगठन और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ।”

(ii) मद सं० 2 के बाद निम्नलिखित मद को अंतर्विष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

मद सं०	रेल सेवकों का वर्ग	रेल सेवक को निम्नलिखित स्थिति में रखने या शास्तियाँ अधिरोपित करने को सशक्त प्राधिकारी तथा शास्ति का स्वरूप
--------	--------------------	--

3	रेल सेवक जिन्हें वर्ग I या वर्ग II जैसे अस्थायी सहायक अधिकारियों में वर्गीकृत न किया गया हो ।	राष्ट्रपति—पूर्ण अधिकार रेलवे बोर्ड—पूर्ण अधिकार महाप्रबन्धक, महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प तथा मानक संगठन और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी— निलम्बन और नियम 6 के उप-नियम (1) के खंड (i), (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियाँ
---	---	--

[सं० ई(डी एण्ड ए) 70 आर जी 6-63]

सी० एस० परमेश्वरन, सचिव रेलवे बोर्ड एवं पदेन संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT  
(Department of Internal Trade)

New Delhi, the 7th June 1971

S.O. 2502.—The following amendments made to the Articles of Association by the Kanpur Oils and Oilseeds Exchange Limited, Kanpur, in exercise of the

powers conferred on it by sub-section (i) of Section 9A of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, (74 of 1952) and approved by the Central Government are hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, namely:—

#### Amendments

In the said Articles of Association:—

1. In Article 9A—

(a) For the existing clause (1) the following shall be substituted:—

“(i) All members of the Exchange shall be classified into three different panels as follows:—

(a) Crushers and Manufacturers Panel.

(b) Growers and Ready Dealers Panel.

(c) Commission Agents and others Panel.

(b) The existing clause (iii) shall be deleted.

(c) The existing clause (iv) shall be renumbered as clause (iii).

(d) The existing sub-clause (a) and (f) of the existing clause (iv) now re-numbered as clause (iii) shall be deleted and the remaining sub-clause (b), (c), (d) and (e) shall be renumbered as sub-clauses (a), (b), (c) and (d).”

2. In Article 50, for the existing (i) (A), the following shall be substituted:—

“(A). Not more than 15 directors elected by the members or their Authorised Representatives in the manner provided for in these presents. (This is the maximum number for elected Directors but the Board may have less number than this if so desired).

Of these Directors:—

(i) Not more than 2 Directors representing Crushers and Manufacturers Panel to be elected by the members or their Authorised Representatives classified in the Crushers and Manufacturers Panel.

(ii) Not more than 2 Directors representing the Growers and Ready Dealers Panel to be elected by the members or their Authorised Representatives classified in the Growers and Ready Dealers Panel.

(iii) Not more than 8 Directors representing the Commission Agents & others panel to be elected by the Members or their Authorised Representatives classified in the Commission Agents & Others Panel.”

[No. 13(1)-I.T.-70.]

P. SITARAMAN, Dy. Secy.

औद्योगिक विकास, औद्योगिक व्यापार तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक वगवार् विभाग)

नई दिल्ली, 7 जून, 1971

का० आ० 2502.—कानपुर आयल एण्ड आयलसीड एक्सचेंज लिमिटेड, कानपुर द्वारा उसे अधिम संबिदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 9क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संगम अनुच्छेद में किए गए, और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन, उक्त धारा की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार एतद्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त संगम-अनुच्छेद में :—

1. अनुच्छेद 9क म :—

(क) विद्यमान खण्ड (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(1) एक्सचेंज के सभी सदस्य तीन विभिन्न पैनलों में निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे :—

(क) पिराई करन वालों और विनिर्माताओं का पैनल ।

(ख) उगाने वालों और तैयार माल के व्यवहारियों का पैनल ।

(ग) कमीशन एजेंट और दूसरों का पैनल ।

(ख) विद्यमान खंड (III) निकाल दिया जाएगा ।

(ग) विद्यमान खंड (4) खंड (III) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा :

(घ) विद्यमान खंड (4) के विद्यमान उप खंड (क) और (ख) जो अब खंड (III) के रूप में पुनः संख्यांकित किए गए हैं, निकाल दिए जाएंगे और शेष उप-खंडों (ख), (ग), (घ) और (ङ) को उपखंड (क), (ख), (ग) और (घ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।”

2. अनुच्छेद 50 में, विद्यमान (1) (क) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(क) इस विलेख में उपाबंधित रीति से सदस्यों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित 15 निदेशकों से अनधिक (यह निर्वाचित निदेशकों के लिए अधिकतम संख्या है किन्तु बोर्ड में इस से भी कम संख्या हो सकती है यदि ऐसा वांछित हो) ।

इन निदेशकों में से :—

(i) पिराई करने वालों और विनिर्माताओं के पैनल का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 से अनधिक निदेशक जो पिराई करने वालों और विनिर्माताओं के पैनल में वर्गीकृत सदस्यों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे :

(ii) उगाने वालों और तैयार माल के व्यवहारियों के पैनल का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 से अनधिक निदेशक जो उगाने वालों और तैयार माल के व्यवहारियों के पैनल में वर्गीकृत सदस्यों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे ।

(iii) कमीशन एजेंट और दूसरों के पैनल का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 से अनधिक निदेशक जो कमीशन एजेंट और दूसरों के पैनल में वर्गीकृत सदस्यों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे :

[सं० 13 (1) प्राई० टी०-70]

प० सीतारामन्, उप सचिव ।

### OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE (Central Excise Wing)

#### CUSTOMS

Cochin, the 8th June 1971

S.O. 2503.—In exercise of the powers conferred by clauses (a) & (b) of Section 8 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) I, L. S. Marthandam, Collector of Customs and Central Excise, Cochin hereby:—

(i) declares that the limits of the port of Neendakara in the State of Kerala shall be:

on the North—A line drawn west from the northern boundary pillar to 10 fathoms of water.

on the south—A line drawn west from the southern boundary pillar to 10 fathoms of water.

on the west—A line joining the western ends of the Northern and southern boundary lines; and

on the East—A line drawn from the northern boundary pillar along the boundary stones 1 to 10 of Neendakara Port to join northern abutment of the Neendakara bridge, thence eastwards along the line



सहायक सचिव (खाद्य अपमिश्रण निवारण), स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशालय, नई दिल्ली को डा० के० बागची के स्थान पर केन्द्रीय खाद्य मानक, समिति का सदस्य मनोनीत किया है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 1236 दिनांक 1 जून, 1955 में आगे और निम्नांकित संशोधन करती है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना में मद—4 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नांकित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, नामतः :

श्री डी० एस० चड्ढा, सहायक सचिव (खाद्य अपमिश्रण निवारण) स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशालय, नई दिल्ली ।

[सं० 14-30/71-जन स्वा]

के० सत्यनारायण, अवर सचिव ।

**MINISTRY OF LAW**  
(Legislative Department)

*New Delhi, the 10th June 1971*

**S.O. 2505.**—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dargah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955), the Central Government, in consultation with the Government of Rajasthan, hereby constitutes, with immediate effect, an Advisory Committee for a period of one year for the purpose of advising the Nazim in the discharge of his functions under the said Act and also for such other purposes as may be specified in the bye-laws of the Dargah Committee, consisting of the following persons, namely:—

1. Shri Mohd. Abdul Hamid Khan, s/o Mohd. Sayeed Khan Saheb of Inderkot, Ajmer.
2. Shri Sayeed Abdul Rauof, s/o Abdul Qaddua Saheb, of Imambara, Ajmer.
3. Shri Sayeed Abdul Baqi, s/o Abdul Khalik Saheb, Hafiz Manzil, Chowk Panngarah, Ajmer.
4. Shri Peer Mohd. Ghoshi, s/o Karimji Saheb, of Delhi Darwaza, Ajmer.
5. Shri Sayed Saulat Hussain Ali Khan, s/o Sayed Inayat Hussain Ali Khan, Dewan Saheb, Dargha, Ajmer.
6. Seth Abdul Karim Allah Rakha Sahib, Qaiser Ganj, Station Road, Ajmer.
7. Sheikhzada Abdul Rashid Sahib s/o Sheikhzada Abdul Latif Sahib, Mohalla Anderkote, Ajmer.

[No. 11(7)/69-Wakf.]

E. VENKATESWARAN, Dy. Secy.

**बिधि मंत्रालय**

**(बिधायी विभाग)**

नई दिल्ली, 10 जून 1971

**का० आ० 2505.**—दरगाह खवाजा साहब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार, राजस्थान सरकार के परामर्श से उक्त अधिनियम के अधीन नाजिम को उसके कृत्यों के निर्वहन में परामर्श के प्रयोजनार्थ और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो दरगाह समिति की उद्दिष्टियों में विनिर्दिष्ट हों, निम्नलिखित व्यक्तियों

को मिलाकर एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा एक सलाहकार समिति का गठन करती है जो तुरन्त प्रभावशील होगा।

1. श्री मोहम्मद अब्दुल हमीद खां सुपुत्र मौ० सईद खां साहब आफ इन्दरकोट अजमेर :
2. श्री सईद अब्दुल रुऊफ सुपुत्र अब्दुल कादर साहब आफ इमामबारा, अजमेर :
3. श्री सईद अब्दुल बाकी सुपुत्र अब्दुल खलिक साहब, हाफिज मंजिल, चौक पनगढ़, अजमेर :
4. श्री पीर मोहम्मद घोषी सुपुत्र करीम जी साहब आफ दिल्ली दरवाजा, अजमेर :
5. श्री सय्यद सोलत हुसैन अली खां सुपुत्र सय्यद इनायत हुसैन अली खां साहब, दीवान, साहब दरगाह, अजमेर :
6. सेठ अब्दुल करीम अल्लाह खन्ना साहिब, क्वेसर गंज, स्टेशन मार्ग, अजमेर :
7. शेखजादा अब्दुल रसोद साहिब सुपुत्र शेखजादा अब्दुल लतीफ साहिब, मोहल्ला एन्डरकोटे, अजमेर :

[सं० 11 (7)/67-अफ]

ई० वेंकटेश्वरन, उप-सचिव।

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

### ORDERS

*Bombay, the 16th April 1971*

**SUBJECT.**—Cancellation of Exchange Control Purpose copy of licence No. 2600334, dated 15th December, 1969 for 13880/- issued in favour of M/s. The New City of Bombay Mfg. Co. Ltd., Bombay-33.

**S.O. 2506.**—M/s. The New City of Bombay Mfg. Co. Ltd., 63 Chinchpokli Road, Bombay-33 have been granted licence No. 2600334 dated 15th December, 1969 for Rs. 13880/- (Thirteen thousand eight hundred and eighty only) for import of Dyes & Chemicals permissible varieties. They have applied for duplicate copy of Exchange Control Purpose copy of the licence on the ground that the original licence has been misplaced.

It is further stated that the said original licence is already utilised for an amount of Rs. 2776/- leaving a balance of Rs. 11,104/-. In support of their claim, the applicant firm have filed an affidavit.

I am satisfied that the original copy of Exchange Control Purpose of the Licence No. 2600334 dated 15th December, 1969 for Rs. 13880/- has been misplaced and direct that the duplicate copy of the said licence should be issued to the applicant firm.

The original licence (Exchange Control Purpose) copy is cancelled.

[Issued from File No. 4/124408/JS.69/L/EPSC.I.B.].



## विदेश व्यापार मंत्रालय

## संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कार्यालय

बम्बई 16 अप्रैल, 1971

विषय : सर्वश्री दी न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० बम्बई-33 के नाम में 13880/- रुपये के लिये जारी किए गये आयात लाइसेंस संख्या फी 2600334, दिनांक 15-12-69 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द करने का आदेश।

का० प्रा० 2506-सर्व श्री दी न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, 63 चिन्चपोकजी रोड, बम्बई 33 को स्वीकृत किस्म के रंगों तथा रसायनों के आयात के लिए 13880/- रुपये (तेरह हजार आठ सौ अस्सी रुपये मात्र) के लिए लाइसेंस संख्या 2600334 प्रदान किया गया था। उन्होंने लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस खो गया है/अस्थानस्थ हो गया है।

आगे यह बताया गया है कि उक्त मूल लाइसेंस का उपयोग 2,776/- रुपये (दो हजार सात सौ छयत्तर) तक किया गया है और यह लाइसेंस मूल्य 11,104/- रुपये (ग्यारह हजार एक सौ चार) बाकी है। अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

मैं इससे संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस संख्या 2600334, दिनांक 15-12-69, मूल्य 13,880 रुपये की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूँ कि उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति आवेदन को जारी की जानी चाहिए।

मूल लाइसेंस (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति) रद्द किया जाता है।

[मिसिल संख्या 4/124408/जे एस० 69/एल/ई पी एससी० आई० बी०-से जारी]

डी० डिस्जा,

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

SUBJECT.—Cancellation of Exchange Control Purpose copy of Licence No. 2606049, dated 11th February, 1970 for Rs. 10,993/- issued in favour of M/s. The New City of Bombay Mfg. Co. Ltd., Bombay-3.

S.O. 2507.—M/s. The New City of Bombay Mfg. Co. Ltd., 63 Chinchpokli Road, Bombay 33 have been granted licence No. 2606049 dated 11th February, 1970 for Rs. 10,993/- (Ten Thousand Nine Hundred and Ninetythree Only for import of Dyes & Chemicals permissible varieties. They have applied for duplicate copy of Exchange Control purpose of the licence on the ground that the original licence has been misplaced.

It is further stated that the said original licence is already utilised for an amount of Rs. 3,318/- leaving a balance of Rs. 7,675/-. In support of their claim, the applicant firm have filed an affidavit.

I am satisfied that the original copy of Exchange Control Purpose copy of the Licence No. 2606049 dated 11th February, 1970 for Rs. 10,993/- has been misplaced and direct that the duplicate copy of the said licence should be issued to the applicant firm.

The original licence (Exchange Control copy) is cancelled.

[Issued from File No. 122/143942/JS.69/L/EPSC.I.B.],

D. D'SOUZA,

Dy. Chief Controller of Imports & Exports,  
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

**विषय :-** सर्वश्री दि न्यू सिटी ऑफ बांबे मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, 93, चिचपोकली रोड, बम्बई-33 के नाम जारी किए गए लाइसेंस सं० 2606049 दिनांक 11-2-70 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द करने का आदेश ।

**फा० आ० 2507--**सर्वश्री दि न्यू सिटी ऑफ बांबे मैन्यूफैक्चरिंग कं० लिमिटेड, 93, चिचपोकली रोड, बम्बई 33 को रंगों तथा रसायनों के आयात के लिए 10,993/- रुपये (दस हजार नौ सौ तरानवें मात्र) के लिए लाइसेंस संख्या 2606049 दिनांक 11-2-70, प्रदान किया गया था । उन्होंने लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस खो गया है / अस्थानस्थ हो गया है ।

आगे यह बताया गया है कि उक्त मूल लाइसेंस सीमा-शुल्क कार्यालयों से पंजीकृत किया गया था और उसका उपयोग 3,388/- रुपये तक किया गया है । और यह लाइसेंस का मूल्य 7,675/- रुपये (सात हजार छः सौ पचहत्तर) बाकी है । अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है ।

मैं इससे सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस संख्या 2606049, दिनांक 11-2-70 मूल्य 10,993/- रुपये की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है / अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस को अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए ।

मूल लाइसेंस (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति) रद्द किया जाता है ।

[मिसिल संख्या 122/143942/जे० एस० 69/एल०/ई० पी० एस० सी०-1-वी० से जारी]

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports)

#### ORDERS

Calcutta, the 24th May 1971

*Order cancelling Customs Clearance Purposes Copy of Import licence No. P/S/8218581/C/XX/35/C/29-30/08/25, dated 7-1-71 in connection with the issue of duplicate copy of the same in terms of G. L. I. No. 10/67 dated 23-3-67.*

**S.O. 2508.**—Messrs. Kalinga Bakery Biscuit Confectionery and Mineral Water Co., Uditnagar, Rourkela, Orissa, were granted Import licence No. P/S/8218581/C/XX/35/C/29-30/80/25, dated 7-1-71 for Rs. 20,485 for import of Electrolytic Tin-plate Waste for manufacture of Tin Containers. They have applied for duplicate copy of the Customs clearance Purposes Copy of the said licence on the ground that the original of the same has been lost/misplaced. It is further stated that original licence was not registered with any Customs House, and full value for the licence i.e. Rs. 20,485/- remains unutilised.

In support of the contention, the applicant has filed one Affidavit to the effect that the original copy of the Customs Clearance Purposes Copy of the licence has been misplaced. I am satisfied that the original Customs Clearance Purposes Copy of the licence No P/S/8218581/C/XX/35/C/29-30/08/25, dated 7-1-71 for Rs. 20,485 has been misplaced and direct that duplicate copy of the same should be issued to the applicant. The original Customs Clearance Purposes Copy of the licence is cancelled.

[No. JCCI&E/I&S/II/08/25/70.]

M. S. PURI,

Dy. Chief Controller of Imports & Exports.  
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports)

(CENTRAL LICENCING AREA)

ORDERS

New Delhi, the 3rd June 1971

**S.O. 2509.**—M/s. Nannu Mal Shyam Sunder, Katra Ishwar Bhawan, Delhi-6 were granted permit No. P/E/0196950, dated 30th January, 1971 valued Rs. 85,029 for import of dry Fruits from Afghanistan under the Indo-Afghan Trade Arrangement 1970-71. They have applied for the duplicate copy of Exchange Control copy of the said permit on the ground that the original copy has been lost/misplaced after having been registered with Ferozepore Custom House and utilized fully.

In support of their declaration, the party has filed an Affidavit duly attested by Notary Public stating that Exchange Control copy of the said permit has been lost/misplaced.

I am satisfied that Exchange Control copy of permit No. P/E/0196950, dated 30th January, 1971 has been lost/misplaced and direct that duplicate copy of Exchange Control copy of the same may be issued to the applicant.

The original Exchange Control Purpose copy of the permit is hereby cancelled.

[No. 21(a) iv/N-2/(8)/A.J.71/Indo-Afghan/CLA.]

M. G. GOMBER,

Dy. Chief Controller of Imports & Exports,  
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 9th June 1971

**S.O. 2510.**—M/s. Phillips Carbon Black Ltd., 'Duncan House' 31, Netaji Subhas Road Calcutta were granted an import licence No. P/C/2049847/A/SH/28/H/27/CGV, dated 23rd July, 1968 for Rs. 50,500/- (Rupees Fifty thousand and five hundred only). They have applied for issue of a Duplicate Customs Purposes Copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes Copy has been lost. It has been further stated by the party that the original Customs Purposes Copy of the import licence was registered with the customs authorities at Calcutta and has been utilised to the extent of Rs. 23,758.66. The duplicate customs copy of the aforesaid import licence is now required for cancelled of a bond executed by the party with the Calcutta Customs at the time of clearance of a consignment valued at Rs. 6,647/- only.

2. In support of the above contention, the applicant has submitted an affidavit. I am, accordingly satisfied that the original customs purposes copy of the said import licence has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7th December, 1955 as amendment the said original customs purposes copy of import licence No. P/C/2049847/A/SH/28/H/27/CGV, dated 23rd July, 1968 issued to M/s. Phillips Carbon Black Ltd., 'Duncan House', 31-Netaji Subhash Road, Calcutta is hereby cancelled.

3. It is also ordered that duplicate of the customs purposes copy of the said import licence may be issued separately to the licensee.

[No. 30(10)/67-68/CG-I.]

H. D. GUPTA,

Dy. Chief Controller of Imports & Exports,  
for Chief Controller of Imports & Exports.

(मुख्य निर्यात, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आवेदन

नई दिल्ली, 9 जून, 1971

क्र० आ० 2510.—सर्वश्री कलिप्स कारबन ब्लैक लि०, इंकन हाउस, 31, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता को 50,500 रुपये (पचास हजार पांच सौ रुपये मात्र) के लिए एक लाइसेंस

सं० पी/सी/2049847 ए/एस/एच/27/सी जी 5, दिनांक 23-7-68 प्रदान किया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रति खो गई है। पार्टी द्वारा आगे यह उल्लेख किया है कि आयात लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति की सीमा शुल्क प्राधिकारी कलकत्ता के कार्यालय में पंजीकृत कराया गया था और उसका उपयोग 23,758, 66 रुपये तक कर लिया गया है। अब पूर्वोक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रति की अनुलिपि की आवश्यकता 6,647 रुपये मात्र के मूल्य के प्रेषित माल की निकासी के समय सीमा शुल्क कार्यालय कलकत्ता के साथ पार्टी द्वारा निष्पादित किए गए बाण्ड को रद्द करने के लिए है।

उपर्युक्त तर्क की पुष्टि में आवेदक ने एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त आयात लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति खो गई है। यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री फिलिप्स का बन् श्लैक लि०, कलकत्ता को जारी किए गए आयात लाइसेंस सं० पी/सी/2049847 ए/एस/एच/28/एच/27 सीजी 5 दिनांक 23-7-68 की उक्त मूल सीमा शुल्क प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

यह भी आदेश दिया जाता है कि लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रति की अनुलिपि अला से जारी की जाए।

[संख्या 3) (10)/67-68/सी० जी० 1.]

हरदेव गुप्ता,

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

## MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 17th April 1971

### ORDERS

**S. O. 2511.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Ballarpur Colliery belonging to the Ballarpur Colliery Company, Post Office Ballarpur, District Chandrapur (Maharashtra) and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri W.K. Almelkar, as Presiding Officer with headquarters at Nagpur and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

### SCHEDULE

Whether the management of Ballarpur Colliery belonging to Ballarpur Colliery Company, Post Office Ballarpur, District Chandrapur was justified in categorising the following workmen as indicated against them? If not, to what relief are the workmen entitled and from what date?

S. No.	Name of the Workmen	Designation
1.	Ibrahim Son of Jahir Khan . . . . .	Supervisor.
2.	Durgaprasad Rambharose . . . . .	P. Khalasi.
3.	Avidhussain Mohd. Hussein. . . . .	W. Driver.
4.	Rampati Rambharose . . . . .	Dresser.
5.	Vidyasag Balgovind . . . . .	Wiremen.
6.	Chandrapagan Vasdeo. . . . .	Supervisor.

[No. 1/55/70-LRII.]

श्रम, रोजगार और पुरुषास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1971

का० प्रा० 2511.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बल्लारपुर कोलियरी कम्पनी, डाकवर बल्लारपुर, जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) की बल्लारपुर कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः श्रम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उल्लू० के० अलमेलकर औद्योगिक अधिकरण होंगे, जिनका मुख्यालय नागपुर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

“क्या बल्लारपुर कोलियरी कम्पनी, डाकवर बल्लारपुर जिला चन्द्रपुर की बल्लारपुर कोलियरी के प्रबंधतंत्र द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दिए गए वर्गों में वर्गीकृत करना न्यायोचित था? यदि नहीं, तो कर्मकार किन अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं?”

क्रमांक	कर्मकार का नाम	पद-नाम
1	इब्राहिम आत्मज जाहिर खां	सुपरवाइजर
2	दुर्गाप्रसाद राम भरोसे	पी० खलासी
3	आबिद हुसैन मोहम्मद हुसैन	उल्लू० ड्राइवर
4	रामपति राम भरोसे	ड्रेसर
5	विद्यासागर बालगोविन्द	वायरमैन
6	चन्द्रपगन वासदेव	सुपरवाइजर

[सं० 1/55/70-एल० आर०-2]

New Delhi, the 21st April 1971

S.O. 2512.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kotma Colliery of Associated Cement Company Limited, Post Office Kotma, District Shahdol (Madhya Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

#### SCHEDULE

"Whether the management of Kotma Colliery of Associated Cement Company Limited, Post Office Kotma, District Shahdol is justified in not placing the Timber Mazdoors in New Category-III as per recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry? If not, to what relief are the workmen entitled and from what date?"

[No. 1/54/70-LR.II.]

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1971

का० प्र० 2512.—यतः केन्द्रीय सरकार को राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, डाकबर कोतमा, जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) को कोतमा कोलियरी के प्रबन्धन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद का न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

#### अनुसूची

"क्या एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, डाकबर कोतमा, जिला शहडोल की कोतमा कोलियरी का कोयला खनन उद्योग के केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार टिम्बर मजदूरों को नई श्रेणी-3 में न रखना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं?"

[सं० 1/54/70-एल० आर०-2]

New Delhi, the 27th April 1971

S.O. 2513.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of New Kenda Colliery, Post Office Toposi, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed:

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

#### SCHEDULE

"Whether the management of New Kenda Colliery, Post Office Toposi, District Burdwan was justified in retrenching Sarvashri Sarbon Singh, Ranjit Singh and Charan Das, Operators and Shri Gurdip Singh, Diesel Mechanic Fitter with effect from the 5th November, 1970? If not, to what relief are they entitled?"

[No. L-1912/26/71-LR.II.]

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1971

का० आ० 2513.—यतः केन्द्रीय सरकार को राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में न्यू कैंदा कोलियरी, डाकवर टोपोसी, जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधीकरण, कलकत्ता यन्त्रिणयन के लिए निर्देशित करती है।

### अनुसूची

“क्या न्यू कैंदा कोलियरी, डाकवर टोपोसी, जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र द्वारा सर्वश्री सर्वोन सिंह, रणजीत सिंह और चरणदास प्रचालकों और श्री गुरुदीप सिंह, डीजल मेकैनिक्स फिटर की 5 नवम्बर, 1970 से छंटनी करना न्यायोचित था? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है?

[सं० एल० 1912/26/71-एल० आर०-2]

New Delhi, the 3rd May 1971

**S.O. 2514.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bankola Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited, Post Office, Ukhra, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

### SCHEDULE

“Whether the management of Bankola Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited, Post Office Ukhra, District Burdwan was justified in effecting the change in shift working of Sarvashri Hari Narayan Bose, T. P. Chatterjee and Narayan Chatterjee, Overmen, Bankola Colliery from 3 shifts to 2nd and 3rd shifts only in rotation from the 3rd July, 1970, 3rd July, 1970 and the 6th July 1970 respectively? If not, to what relief the workmen concerned are entitled?”

[No. 6/80/70-LRIL]

नई दिल्ली, 3 मई, 1971

का० आ० 2515.—यतः केन्द्रीय सरकार को राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बुराकुर कोल कम्पनी लि० डाकवर उखड़ा, जिला बर्दवान की बंकोला कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

#### अनुसूची

“क्या मैसर्स बुराकुर कोल कम्पनी लि०, डाकघर उखड़ा, जिला बर्दवान के प्रबन्धक द्वारा सर्वश्री हरितारायण बोस, टी० पी० चटर्जी और नारायण चटर्जी, श्रीवरमेन, बंकोला कोलियरी के पारी-कार्य में, क्रमशः तीन पारियों से केवल दूसरी और तीसरी पारी में 3 जुलाई, 1970, 3 जुलाई, 1970 और 6 जुलाई, 1970 से बारी-बारी से परिवर्तन करना न्यायोचित था? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?”

[सं० 6/80/70-एल० आर०-2]

S.O. 2515.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial disputes exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kothagudem Collieries (Andhra Pradesh) and their work men in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri T. Chandrasekhara Reddy, as Presiding Officer with headquarters at Afzal Lodge, Tilak Road, Ramkote, Hyderabad-1, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

#### SCHEDULE

“Whether the management of Godavari Khani No. 6 Incline of Messrs Singareni Collieries Company Limited is justified in placing Shri Gangarapu Odely, Tyndal in Category IV as per Wage Board recommendation, if not, to what relief is the workman entitled and from what date?”

[No. L/2112/6/71LRIL]

क० आ० 2515.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, डाकघर कोथागुडम कोलियरीज (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबन्धक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान,

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० चन्द्रसेखर रेड्डी होंगे, जिसका मुख्यालय अफजल लॉज, तिलकोट रोड रामकोटे, हैदराबाद-1 होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

#### अनुसूची

“क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड की गोदावरी खनि न० 6 इन्क्लाइन के प्रजातंत्र का श्री गंगारपु ओडेली टिडल को मजदूरी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार श्रेणी-4 में रखना न्यायोचित है; यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का और किस तारीख से हकदार है।”

[सं० एल०/2112/671-एल० आर०-2]



New Delhi, the 4th May 1971

**S.O. 2516.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Samla Colliery, Post Office Pandaveshwar, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under Section 7A of the said Act.

#### SCHEDULE

"Whether the management of Samla Colliery, Post Office Pandaveshwar, District Burdwan was justified in stopping from work Sarvashri Balendra Roy, Pump Khalasi, Tarapada Acharaya, Shot-firer, Madhob Pal, Shot-firer Mazdoor and Sarvashri Bahadur Roy, Narayan Ghosh, Pado Bouri, Ram Bouri, Bibaran Bouri and Gora Chandra Monda, Bhota Dasoih, General Mazdoor with effect from the 8th October, 1969? If not, to what relief are they entitled?"

[No. 1/1912/35/71-LRII.]

नई दिल्ली, 4 मई, 1971

का० आ० 2516.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सामला कोलियरी, डाकघर पांडवेश्वर, जिला बर्दवान के प्रबन्धनत्व से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

#### अनुसूची

"क्या सामला कोलियरी, डाकघर पांडवेश्वर, जिला बर्दवान के प्रबन्धनत्व द्वारा सर्वश्री बालेन्द्र राम, पम्प खलासी, तारापद आचार्य, शॉट-फायरर, माधोब पाल, शॉट फायरर मजदूर और सर्वश्री बहादुर राय, नारायण घोष, पादो बाउरी, राम बाउरी, बिबार पी बाउरी और गोगा चन्द्र मोंडा, भोंटा दुसाध, सामान्य मजदूर को 8 अक्तूबर, 1969 से काम से रोकना न्यायोचित था? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुशेष के हकदार हैं?"

[सं० एल० 1912/35/71-एल० आर०-2]

New Delhi, the 5th May 1971

**S.O. 2517.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kothagudem Collieries (Andhra Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the

Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri T. Chandra-sekhara Reddy, as Presiding Officer with headquarters at Afzal Lodge, Tilak Road, Ramkote, Hyderabad-1, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

#### SCHEDULE

"Whether the management of Singareni Collieries Company Limited, Belampalli Division, No. 2 Incline is justified in terminating the services of Shri Durgam Buchodu, Trammer for over-stayal of leave beyond the 19th March, 1968 without making payment of gratuity? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. 7/33/70-LR.II.]

नई दिल्ली, 5 मई, 1971

का० आ० 2517.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०, डाकघर कोटागुडेम कोलियरीज (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० चन्द्रसेखरा रेड्डी होंगे, जिनका मुख्यालय अफजल लोड, तिलक रोड, रामकोटे, हैदराबाद-1 होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण, को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

#### अनुसूची

"क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० बेलमपल्ली प्रभाग संख्या 2 इन्क्लाइन के प्रबंधतंत्र द्वारा श्री दुर्गम बुचोडु ट्रैम्मेर की सेवायें, 19 मार्च, 1968 के बाद छुट्टी बढ़ाने के कारण ग्रेज्युटी दिए बिना समाप्त करना न्यायनिर्णयन है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ।

[सं० 7/33/70 एल० आर०-2]

S.O. 2518.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of East Basuria Colliery of Messrs The East Basuria Colliery Company Private Limited, Post Office Khusunda, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act,

#### SCHEDULE

"Whether the action of the management of East Basuria Colliery of Messrs The East Basuria Colliery Company Private Limited, Post Office Khusunda, District Dhanbad, in dismissing Shri Chandra Das, Loco Driver from service with effect from the 7th January, 1971 is justified? If not, to what relief is he entitled?"

[No. L-2012/47/71-LR.II.]

का० आ० 2518.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स दि ईस्ट बसुरिया कोलियरी कम्पनी प्राइवेट लि० की ईस्ट बसुरिया कोलियरी, डाकघर कुसुन्डा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

### अनुसूची

“क्या मैं तब दि ईस्ट बसूरिया कोलियरी कम्पनी प्राइवेट लि० की ईस्ट बसूरिया कोलियरी, डाकघर कसुन्डा, जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र द्वारा श्री चन्ना दास, लोको चालक को 7 जनवरी, 1971 से तौकरी में परव्युक्त करने की करवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।”

[ सं० एल०-2012/47/71-एल० आर०-2 ]

**S.O. 2519.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bankola Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited, Post Office Ukhra, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

### SCHEDULE

“Whether the management of Bankola Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited, Post Office Ukhra, District Burdwan was justified in stopping from work from the 4th October, 1969 and dismissing from the 24th November, 1969 Sarvashri Jetha Majhi, Brij Mohan Chowhan, Narthu Chowhan, Noor Mohammad, Kandana Majhi, Ramkar Gope, Sarajit Joiswara and Dhanai Singh, Dressors of Bankola Colliery? If not, to what relief the workmen concerned are entitled?”

[No. L/1912/28/71-LRII.]

का० आ० 2519.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बुराकुर कोल कम्पनी लि० की बंकोला कोलियरी, डाकघर उखरा, जिला बर्दवान के प्रबंधतंत्र में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

**अनुसूची**

“क्या मैसर्स बुराकिर कोल कम्पनी लि० की बंकोला कोलियरी, डाकघर उखरा, जिला बर्दवान के प्रबंधन द्वारा बंकोला कोलियरी के सर्वथी जेठा भास्त्री, ब्रिजमोहन चौहान, नथु चौहान, नूर मोहम्मद, कन्दन भास्त्री, रामकर गोप, सराफजीत जोइसवारा और घनेमिह, डैसरो को 4 अक्टूबर, 1969 में काम से रोकना और 24 नवम्बर, 1969 से पदच्युत करना न्यायोचित था? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?”

[सं० एल०-1912/28/71-एल० आर०-2]

*New Delhi, the 7th May 1971*

**S.O. 2520.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kumarkhala Colliery, Post Office Bahula, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

**SCHEDULE**

“Whether the management of Kumarkhala Colliery, Post Office Bahula, District Burdwan was justified in not providing proper category and in terminating the employment of Sarvashri Hari Bouri, Blacksmith Mistry, Anil Bouri Hammerman, Mangal Gope, Belloman, Prahiad Bouri, Tub repairer and Alhad Bouri, Tub repairer helper with effect from the eighteenth November, 1970? If not to what relief are the workmen entitled and from what date?”

[No. L-1912/4/71-LRII.]

नई दिल्ली, 7 मई, 1971

**का० आ० 2520.**—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कुमारखाला कोलियरी, डाकघर बाहुला, जिला बर्दवान के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

**अनुसूची**

“क्या कुमारखाला कोलियरी, डाकघर बाहुला, जिला बर्दवान के प्रजातन्त्र का सर्वथी हरि बोरी, लोहार मिस्त्री, अनिल बोरी, हेमरमैन, मंगल गोप, वेल्लोमैन, प्रहलाद बोरी, टब मरम्मतकर्ता और प्रलहाद बोरी, टब मरम्मतकर्ता सहायक को समुचित वर्ग न देना और अठारह नवम्बर, 1970 से उनकी रोजगार समाप्त करना न्यायोचित था? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं?”

[सं० एल०-1912/4/71-एल० आर०-2]

New Delhi, the 11th May 1971

**S.O. 2521.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jaipuria Kajora Colliery, Post Office Andal, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

## SCHEDULE

“Whether the management of Jaipuria Kajora Colliery Post Office Andal, District Burdwan was justified in not declaring the following workmen as permanent? If not, to what relief are they entitled and from what date?”

Names of workmen	Designation
1. Shri Ranjit Talukadar . . . . .	Timber Mazdoor
2. Shri Kartick Banerjee . . . . .	Lamp Issuer.
3. Shri Manu Gope . . . . .	Linc Mazdoor.
4. Shri Karuna Dey . . . . .	Bailing Mazdoor.
5. Khudiram Bouri . . . . .	Trammer.
6. Sarga Bouri . . . . .	Trammer.

[No. L-1912/27/71-LR- II]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

नई दिल्ली, तारीख 11 मई 1971

का० प्रा० 2521.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में जयपुरिया कजोरा कोलियरी, डाकघर अंदाल, जिला बर्दवान के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधिन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

## अनुसूची

“क्या जयपुरिया कजोरा कोलियरी डाकघर अंदाल, जिला बर्दवान के प्रबंधतंत्र का निम्नलिखित कर्मकारों को स्थायी घोषित न करना न्यायोचित था ? यदि नहीं, तो वे किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं ?”

कर्मकारों का नाम

पदनाम

1- श्री रंजीत तालुकदार	काष्ठ मजदूर
2- श्री कार्तिक बनर्जी	लैम्प देने वाला
3- श्री मोन गोप	लाइन मजदूर
4- श्री करुणा डे	बेलिंग मजदूर
5- खुदीराम बौरी	टैम्पर
6- सर्गा बौरी	टैम्पर

[सं० एल-1912 / 27 / 71-एल आर-2]

आर० कुंजिथापदम, अव्वर सचिव ।

## (Department of Labour and Employment)

## ORDER

New Delhi, the 10th February 1971

S.O. 2522.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kothagudium Collieries (Andhra Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri T. Chandrasekhara Reddy, as Presiding Officer with headquarters at Afzal Lodge, Tilak Road, Ramkote, Hyderabad-1, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Kalyan Khani Workshop, Mandamari Division, Singareni Collieries Company Limited, in not granting Category VI (New) and Category V (New) to Sarvashri Mohammad Gouse and Mohammad Roza, Armature Winders, respectively, as per the recommendations of the Wage Board for Coal Mining Industry, is justified? If not, to what relief are the workmen entitled and from what date?"

[No. 7/28/70-LRII.]

U. MAHABALA RAO, Dy. Secy.

(अभ्य और रोजगार विभाग)

## आदेश

नई दिल्ली, 10 फरवरी 1971

का० प्रा० 2522.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, डाकघर कोठागुडियम कोलियरीज (आंध्र प्रदेश) से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7—क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० चन्द्रशेखर रेड्डी होंगे, जिनका मुख्यालय अफ़ज़ल लौज, तिलकोटे, रामकोटे, हैदराबाद-1 होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

## अनुसूची

"क्या कल्याण खानि कर्मशाला, मांडामारी खंड, सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, के प्रबन्धतंत्र की सर्वश्री मुहम्मद गोस और मुहम्मद रोज़ा, ग्रामाच्योर बांडवर्ज को कोयला खनन उद्योग संबंधी मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार प्रवर्ग-6 (नया) और प्रवर्ग 5 (नया) न देने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार है ?"

[सं० 7/28/70—एल० आर०—2]

यू० महाबला राव, उप सचिव।

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 16th April 1971

**S.O. 2523.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of Bikaner and Jaipur and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal. No. 2, Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur in terminating the services of Shri Suresh Mishra, Clerk with effect from the 8th July, 1970 was justified? If not, to what relief is he entitled?

[No. 23/136/70/LR.III.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

(अस और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अप्रैल 1971

का० आ० 2523—यतः केन्द्रीय सरकार कि राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के तारे में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्धतन्त्र की श्री सुरेश मिश्र, लिपिक की, 8 जुलाई, 1970 से, सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है?"

[सं० 23/136/70-एल० आर० 3]

एस० एस० सहस्र नामन, अवर सचिव ।

(Department of Rehabilitation)

(Office of the Chief Settlement Commissioner)

New Delhi, the 7th June 1971

**S.O. 2524.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the Displaced Persons Compensation and Rehabilitation Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints in supersession of Notification No. 3(16)/

L&R/69 dated 2-3-71, the Under Secretary (Revenue) of the Government of Himachal Pradesh, as Settlement Commissioner for the purpose of performing, in addition to his own duties as Under Secretary (Revenue) Government of Himachal Pradesh, the functions assigned to a Settlement Commissioner, by or under the said Act in respect of acquired evacuee urban and rural properties and urban and rural agricultural lands forming part of the Compensation Pool, transferred to the State Government in 'package Deal' or under Administrative and financial arrangements.

[No. 3(16)/L&R/69.]

D. KRISHNA AYYAR, Jt. Secy

**(पुनर्वास विभाग)**

मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त कार्यालय

नई दिल्ली, 7 जून, 1971

का० आ० 2524.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अधिसूचना संख्या 3 (16) एल० तथा आर०/69 दिनांक 2-3-1971 का अतिक्रमण करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के अवसरसचिव (राजस्व) को हिमाचल प्रदेश के अवसरसचिव के कार्यों के अतिरिक्त उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत "पैकेज डील" या प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थाओं के अधीन राज्य सरकार को हस्तान्तरित प्रतिकर पूल की अर्जित निष्क्रान्त शहरी तथा ग्रामीण सम्पत्तियों और शहरी तथा ग्रामीण कृषि भूमियों के सम्बन्ध में बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गये कार्यों को करने के लिए बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 3(16) एल एण्ड आर/69]

ध० कृष्णा अय्यर,

भारत सरकार के संयुक्त सचिव तथा

मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त।

**(Department of Labour and Employment)  
[Office of the Chief Labour Commissioner (Central)]**

**ORDER**

*New Delhi, the 8th June, 1971*

S.O. 2525.—Whereas an application has been made under section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs. Lower Kenda Colliery (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 30th June, 1970.

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. WB. 20(42)/65 dated the 28th August, 1965, passed order on 8th June, 1970 extending the period for payment of the said bonus by the said employer by four months (i.e. up to 30th June, 1970) from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

**THE SCHEDULE**

Name and address of the employer(s)	Establishment
M/s. Lower Kenda Colliery, Khas Kenda Colliery Pvt. Ltd., P.O. Kajoragram, Dist. Burdwan.	

[No. BA-5(8)/71-LSI.]

O. VENKATACHALAM,

Chief Labour Commissioner (Central).



(श्रम और रोजगार विभाग)

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून 1971

का० आ० 2525.—यतः मैसर्स लोअर केन्डा कोलीयरी (नियोजक) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के संबंध में 30-6-1970 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवेदन दिया है।

और यहतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण हैं, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० डब्ल्यू बी-20(42)/65, तारीख 28 अगस्त, 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8-6-71 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन बोनस के संदाय की अन्तिम तारीख से 4 महीने (अर्थात् 30-6-71 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

**अनुसूची**

नियोजक/नियोजकों का नाम और पता

मैसर्स लोअर केन्डा कोलीयरी, खास केन्डा कोलियरी (प्रा०) लि०,

प० आ० कजोरा ग्राम, बर्दवान।

[सं० बी० ए० 2(8)/71 एल० एस० 1]

श्री० वेंकटावलम,

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)।

**(Department of Labour and Employment)**

*New Delhi, the 21st June 1971*

S.O. 2526.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of Shri B. S. Sachdev, Assistant Labour Commissioner (Central), Asansol, Arbitrator, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New Damagoria Colliery, Post Office Salanpur, District Burdwan and their workmen which was received by the Central Government on the 15th June, 1971.

BEFORE SHRI B. S. SACHDEV, ASSISTANT LABOUR COMMISSIONER(C) AND ARBITRATOR.

**PRESENT:**

Shri B. S. Sachdev, Assistant Labour Commissioner (Central), Asansol.

**PARTIES:**

Employer in relation to New Damagoria Colliery of M/s. New Damagoria Coal Company (P) Ltd., P.O. Salanpur, Dist. Burdwan.

*Vs.*

Their workmen represented by Colliery Mazdoor Congress (HMS), Md. Hussain Street, Bengal Hotel, Asansol.

*Appearance. for employers.*—Shri P. N. Chaturbedi, Chief Personnel Officer, M/s. New Damagoria Coal Co. (P) Ltd., P.O. Salanpur, Dist. Burdwan.

*Appearance for workmen:*—Shri T. N. Chakravorty, Vice-President, Colliery Mazdoor Congress (HMS), Md. Hussain Street, Bengal Hotel, Asansol.

INDUSTRY: Coal

DISTRICT: Burdwan.

### AWARD

The Central Government having received the arbitration agreement dated 26th November, 1970 between the management of New Damagoria Colliery of M/s. New Damagoria Coal Company (P) Limited, P.O. Salanpur, Dist. Burdwan (hereinafter referred to as the management) and their workmen represented by Colliery Mazdoor Congress (HMS), Asansol, Dist. Burdwan (hereinafter referred to as the union) in pursuance of Sub-Section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referring the Industrial Dispute between them, the specific matters in dispute as given below for my arbitration, and Central Government being of the opinion that the industrial dispute referred to above exists between the management and the union, ordered publication of the aforesaid arbitration agreement in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section 2(i) under their order No. 8/206/70-LR-II, dated the 23rd February, 1971:—

#### *"Specific matters in dispute"*

"Whether the management of New Damagoria Colliery of the New Damagoria Coal Co. (P) Ltd., P.O. Salanpur, Dist. Burdwan was justified in retrenching the following 19 workmen with effect from 23rd June, 1970? If not, to what relief are these workmen entitled?"

1. Sri Mukhram Shah.
2. Sri Ramprasad Shah.
3. Sri Morai Sha.
4. Sri Anrudh Bhuniya.
5. Sri Dinanath Gareri.
6. Sri Siyaram Munia.
7. Sri Ramashankar Ram.
8. Sri Trijugi Narayan Goreri.
9. Sri Umashankar Koiri.
10. Sri Dukhit Ram.
11. Sri Kayda Hossain.
12. Sri Marhangi Nunia.
13. Sri Md. Islam Mia.
14. Sri Md. Idrish Mia.
15. Sri Ch. Ram Prasad Shah.
16. Sri Joynath Gareri.
17. Sri Golap Harijan.
18. Sri Prahlad Teli.
19. Shrimati Sam Bai.

2. Though in terms of arbitration agreement signed on 26th November, 1970 it was agreed by the parties that the arbitrator shall make his award within a period of six months or within such further time as is extended by mutual agreement between them in writing, the parties filed a petition during the course of the arbitration proceedings on 4th May, 1971 to extend the said period by one month, thus enabling me to give my award by 26th June, 1971.

3. The stand of the union in brief as taken in the written statement filed by them is that the 19 workmen involved in this dispute were illegally stopped from work by the management on 23rd June, 1970 and they come to know about the alleged retrenchment by the management only in the course of joint discussion held before the Assistant Labour Commissioner (C). The union challenged the retrenchment on the ground that these workmen were not surplus to the requirement at the colliery and that the statutory procedure was not followed by the management while effecting the pretended retrenchment and that the said management was recruiting many workmen in the colliery for working as general mazdoors and wagon loading mazdoors and though the workmen involved in this dispute were fit for employment in those jobs, they were not

provided with such jobs and consequently prayed for holding the action of the management as unjustified and for directing them to reinstate the workmen as general mazdoors at the colliery with full wages for the period of their unemployment.

4. The case of the management as stated in their written statement is that they were employing 212 workmen on the work of overburden removal and such workmen were known as Dalla Workers and Godi Workers, that the management decided to stop the overburden removal work as a large area of coal was exposed and the coal was of poor quality and was not easily saleable, that accordingly 193 such workmen voluntarily left the colliery after accepting full and final payment including *ex-gratia* amount equivalent to retrenchment compensation, that the remaining 19 workmen in dispute were issued notice of retrenchment on 23rd May, 1970 intimating them that their services would stand terminated from 23rd June, 1970 and that the said retrenchment was legal and proper. The management *inter alia* denied the allegations of the union made in their written statement either because those were alleged to be not true or not relevant and consequently prayed for upholding the said retrenchment without any relief to the workmen.

5. Both the parties filed various documents in support of their respective case. The documents filed by the management have been marked as Ext. M-1 to Ext. M-6 while those filed by the union are marked as Ext. W-1 to Ext. W-7. The union produced only one witness namely Shri Ramshankar (UW-1) one of the retrenched workmen involved in this dispute while the management produced two witnesses namely Shri B. B. Roy, Manager of the Colliery (MW-1) and Shri N. J. Jani Cashier of the Colliery, (MW-2).

6. A careful perusal and scrutiny of all the documents as well as oral evidence adduced by both the parties it is clear that the work of overburden removal at the colliery was stopped on and from 23rd June, 1970 and it continues to remain so. Further all the workmen employed at the work of overburden removal other than the 19 workmen involved in this dispute, have already left their services from the colliery after receiving full and final payment of their dues including *ex-gratia* payment. It is further brought out by the management that the notices for retrenchment (Ext. M-1) were issued to the 19 workmen on 23rd May 1970 under Certificate of Posting (Ext. M-2) giving them one months notice and retrenching their services on and from the 23rd June, 1970. In the same notice these workmen were called upon to collect their dues and retrenchment compensation on 23rd June, 1970 during office hours from the cashier. Ext. M-3 is an intimation received by the A.L.C.(C), Asansol in form "P" under the Industrial Disputes (Central) Rules, 1956 addressed to the Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation, New Delhi with a copy to the RLC(C), Asansol and him. This notice though dated 31st July, 1970 was received in the office of the ALC(C) Asansol on 7th August, 1970. The management have duly accepted the delay in the submission of this notice both in their written statement as well as in the oral evidence of Shri B. B. Roy (MW-1) on grounds of inadvertency. Though notice dated 23rd May, 1970 (Ext. M-1) does not indicate the reasons of retrenchment, the notice in form "P" (Ext. M-3) does incorporate the reasons which are re-produced below:—

"Stoppage of overburden removal work from 23rd June, 1970 and earth cutting work due to non-saleability of coal in the market, difficult mining operations, continued uneconomic working of the colliery and for reasons beyond the control of the management."

Similar reasons have been adduced by the management in their written statement as well as the oral evidence of MW-1. It is further brought out by the management during the course of evidence of their witnesses that the work of overburden removal was stopped as per negotiations between them and the representatives of the workmen but the 19 workmen involved in this dispute did not agree to act accordingly to that understanding which was agreed to by others. It was for this reason that these workmen had to be issued retrenchment notice in question. The only union witness Shri Ramshankar stated that he did not receive any notice dated 23rd May, 1970 (Ext. M-1) and came to know about the termination of his service only after he received a Registered letter dated 1st August, 1970 (Ext. W-7) from the management. He however stated that he was stopped from work from 23rd June, 1970 alongwith other 18 workers involved in this dispute. He admitted that no workers were employed on the work of over-burden removal from 23rd June, 1970. According to him other workmen employed on this work left after resignation and after receiving full and final payment. As because he did not resign, he did not take any full and final payment from the management.

7. In view of the above mentioned position of the case, the issues which arise out for any consideration are whether the retrenchment of the 19 workmen involved in the dispute was affected in accordance with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 and that this retrenchment was justified.

8. Under section 25 of the I.D. Act, 1947 the management is required to fulfil the conditions laid down therein which are precedent to retrenchment of any worker employed in an industrial establishment. These conditions are reproduced below:—

"25-F. Conditions Precedent to retrenchment of Workmen—No workmen employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—

- (a) the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice wages, for the period of the notice:

Provided that no such notice shall be necessary if the retrenchment is under an agreement which specifies a date for the termination of service;

- (b) the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service of any part thereof in excess of six months; and

- (c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified by the appropriate Government by notification in the official Gazette."

As already brought out by the management in their evidence on record, a notice dated 23rd May, 1970 (Ext. M. 1), was duly served on the workman concerned under Certificate of Posting (Ext. M. 2). In the said notice one month's notice was given to these workmen for terminating their service and the retrenchment compensation in accordance with the condition at (b) above was also duly offered. Though the union witness has denied receipt of any such notice, he duly admitted that he, along with other 18 workmen, was stopped from work from 23rd June, 1970. He also stated that the work of over burden removal was closed from 23rd June, 1970. Ext. W. 7 filed by him during the course of his evidence relates to Shri Haringi Mia, another workman involved in this dispute, though he has stated in his evidence that he came to know of his termination when he received this letter. This is rather strange. It may be a mistake on his part to file a wrong letter. But in any case I cannot take any cognizance of the letter which does not relate to this workman and remains unproved. Nothing further has been placed before me to substantiate the claim of this witness that he did not know about his termination from 23rd June, 1970 in spite of management's notice dated 23rd May, 1970 (Ext. M. 1) and the certificate of posting (Ext. M. 2). There is also inconsistency in the stand of the union on this question, while this witness refers to the letter (Ext. W. 7) for knowing about his retrenchment, the union in its written statement stated that these workmen came to know of this fact during the course of joint discussion before the ALC(C), Asansol, when the dispute about their alleged illegal stoppage was referred for his intervention. For all these reasons I cannot but accept the evidence placed by the management before me regarding issue of notice of termination. The condition at (a) also states that the notice should also indicate the reasons for retrenchment. It is observed that the notice in his case (Ext. M. 1) does not mention any reasons. In this connection M.W. 1 Shri B. B. Roy has stated that the work of over burden removal was stopped as per negotiations between the management and representatives of the workmen and as because these 19 workmen did not agree to act according to that understanding which was agreed to by the rest of the workmen, they had to be issued the notice of retrenchment. This piece of evidence remains un rebutted by the union. Further the notice in form "P" (Ext. M. 3) clearly indicates the reason of this retrenchment. In view of these, I am of the view that the omission of reasons in the notice of retrenchment (Ext. M. 1) does not in any way vitiate this retrenchment. In the circumstances I hold that the condition at (a) above was duly fulfilled by the management. Further it is duly admitted by the union's witness that he did not accept the full and final payment when others accepted this payment because he did not resign. The evidences of Shri Jani (M.W. 2) further proves that the payment of these final dues was duly offered to the retrenched workmen but they did not accept any money on 23rd June 1970. All this clearly shows that the retrenchment compensation mentioned in the management's letter dated 23rd May, 1970 (Ext. M. 1) was duly offered to these retrenched workmen also but this was not accepted by them. Thus the condition at (b)

referred to above has been duly fulfilled by the management. Regarding the condition at (c) above the management has duly admitted delay in their submission of the prescribed notice in form "P". This has been explained to be due to reasons of inadvertence. The said notice, though signed on 23rd May, 1970 by the Manager of the Colliery was despatched on 31st July, 1970 and received in the office of the ALC(C), Asansol on 7th August, 1970. This delay however does not in my view vitiate the retrenchment notice served on the workmen, as because the condition at (c) cannot for all practical purposes be considered as precedent to retrenchment like those at (a) and (b). In this view, I am supported by the judgment of the Supreme Court in Civil Appeal No. 497 of 1963 dated 19th December, 1963 in the case between Bombay Union of Journalists vs. State of Bombay reported at 351-357-J-LLJ 1964. The Supreme Court while examining this issue directly in the above mentioned case held as under:—

"Therefore having regard to the object which is intended to be achieved by clauses (a) and (b) as distinguished from the object which clause (c) has in mind, it would not be unreasonable to hold that clause (c) unlike clause (a) and (b) is not a condition precedent".

Thus it would be clear that the management had duly observed all the condition laid down under Section 25F of the I.D. Act, 1947 while retrenching workmen involved in this dispute.

9. As will be clear from the evidence on record, the work of over burden removal was stopped from 23rd June, 1970. The notice dated 31st July, 1970 (Ext. M. 3) duly gives reasons for effecting the retrenchment of the workmen in question. These reasons have been corroborated by the evidence of the witnesses belonging to the management. Both the management and the union witnesses have stated that the work of over burden removal was stopped from 23rd June, 1970 and continues to remain stopped and further that all the workmen other than these 19 workmen have already left after receiving their full and final payment. It is no doubt an inherent right of the management to consider what work is to be undertaken at a particular time and what number of workmen has to be employed for the purpose. In view of these reasons it is certainly not possible to give any relief to these retrenched workmen. The management being the best judge to decide the organizational matters of their business including the question of surpluse of labour, I have no reasons to consider this retrenchment as unjustified, especially when it is not the case of the union that these workers were in any way victimised or that the retrenchment was mala fide. They have also not led any evidence to prove that they were not the junior most workmen on the date of issuing of the notice of retrenchment, even though on that date the remaining workmen employed on over-burden removal work were still in employment.

10. In their written statement the union has in fact prayed for re-instatement of these workmen as General Mazdoors. There is some evidence to prove that these workmen had at times been employed on alternative jobs like wagon loading etc. though there is nothing to suggest that their substantive appointment was as General Mazdoors. On the other hand it is proved beyond doubt by the evidence on record of both the management and the union that these workmen were substantially employed on the work of over burden removal, which remains discontinued at the colliery. I am therefore unable to give them the relief sought for by the union.

11. For the reasons detailed above, I am of opinion that the management was justified in retrenching the workmen involved in this dispute from service with effect from 23rd June, 1970 and so they are not entitled to any relief and that is my award.

ASANSOL,  
Dated the 10th June 1971

(Sd.) B. S. SACHDEV,  
Assistant Labour Commissioner (C), Asansol  
and Arbitrator.

[No. 8/206/70-LR.II]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

